राजेंद्र कुमार किंद्रवी.

दिल्ली प्रशासन के माध्यम से

सचिव (श्रम) और ओआरएस।

7 सितंबर, 1984

[डी. ए. देसाई और डी. पी. मैडन, जे. जे.]

औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947-धारा 11-एमध्यस्थ और न्यायालय घरेलू जांच में दिए गए सबूतों का पुनर्मूल्यांकन कर सकता है संतुष्ट करें कि क्या कर्मचारी के खिलाफ कदाचार साबित हुआ है। मध्यस्थ और न्यायालय कदाचार के साक्ष्य को अस्वीकार कर सकते हैं बिना किसी कानूनी सबूत के,

भारत का संविधान-अनुच्छेद 136-उच्चतम न्यायालय कर सकता है बिना किसी कानूनी साक्ष्य के आधार पर कदाचार के निष्कर्षों को अस्वीकार करें।शब्द और वाक्यांश-कदाचार-चाहे अपना रखना चेक बुक का लावारिस रहना कदाचार की श्रेणी में आता है कर्मचारी।

लाभकारी रोजगार-क्या है-रोजगार के अभाव में अपने ससुर के साथ रहना और उनके काम में मदद करना है लाभकारी रोजगार नहीं.

अभिनिर्धारित किया:-

अपीलकर्ता एक शोरूम में सेल्समैन के रूप में काम कर रहा था। कंपनी ने अपीलकर्ता के खिलाफ कदाचार के आधार पर आरोप पत्र दायर किया। अपीलकर्ता का कहना था कि उसने अपने निजी खाते के संबंध में चेक-बुक रखने में लापरवाही बरती है, इस प्रकार शोरूम, जिसमें अपीलकर्ता सेल्समैन था, के प्रबंधक-सह-कैशियर को है, उक्त समय पर चेक प्रपत्रों का दुरुपयोग करने एवं धोकधड़ी करने में सक्षम था।

आरोपों की जांच करने हेतु एक जांच अधिकारी नियुक्त किया गया। कंपनी ने मामले की जांच की और साक्ष्य प्रस्तुत किये गये। जांच अधिकारी ने सभी आरोपों में अपीलार्थी को दोषी पाया। जांच अधिकारी के निष्कर्षों के आधार पर कंपनी ने अपीलकर्ता को सेवा से बर्खास्त कर दिया। अपीलकर्ता ने एक औद्योगिक विवाद दायर किया तथा वह,एक क़रार द्वारा, उपयुक्त सरकार द्वारा औद्योगिक विवाद अधिनियम,1947 की धारा 10(ए)(1) के अंतर्गत एक मध्यस्थ को संदर्भित किया गया। कंपनी ने कहा कि मध्यस्थ जांच के निष्कर्षों पर अपील में नहीं बैठ सकता। उनके पुरस्कार में, मध्यस्थ ने माना कि जांच अधिकारी के निष्कर्ष ये बिना किसी कानूनी सबूत पर आधारित थे और इसलिए, विकृत और इसलिए जांच ख़राब हो गई थी। इसके पहले औपचारिक अंतिम आदेश मध्यस्थ द्वारा दिया जा सकता था,वे दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत हो गए थे। जिसके कारण एक दूसरा रेफ़्रेन्स दायर किया गया। दूसरे मध्यस्थ

ने अपीलकर्ता को सभी आरोपों में दोषी मानते हुए कहा कि अपील की बर्खास्तगी ग़लत नहीं थी। अपीलार्थी ने अनुछेद 226 के अधीन हाई कोर्ट में रिट याचिका दायर की।

पुरस्कार की शुद्धता,वैधता और वैधानिकता तथा दूसरे मध्यस्थ के अवार्ड के विरुद्ध संविधान के अनुछेद 226 के अंतर्गत एक रिट याचिका दायर की गयी। उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने मामले को इस आधार पर सिरे से खारिज कर दिया की साक्ष्य के मूल्यांकन पर निर्भर करता है और न्यायालय संविधान के अनुछेद 226 के अधीन उसका पुनर्मूल्यांकन नहीं कर सकता।

अतः विशेष अनुमति द्वारा यह अपील।

अपील स्वीकार करते हुए, अभिनिर्धारित अपीलकर्ता के खिलाफ लगाया गया आरोप समग्र आवेश है और इसके दो अंग हैं। पहला अंग आरोप का तात्पर्य उनके निजी चेकबुक को संभालने में लापरवाही से है ताकि मैनेजर के साथ साजिश कर फॉर्म की जांच कर सकें अपीलकर्ता को जारी चेक-बुक में निहित है प्रबंधक द्वारा अपने निजी खाते का संचालन करने के लिए उपयोग किया जाता था कंपनी को धोखा देना. जब किसी को चेक-बुक जारी की जाती है बैंक द्वारा खाता धारक के लिए कोई कानून नहीं है उसे अपनी चेक-बुक सुरक्षित अभिरक्षा में रखनी होगी। वह शायद कर सकता है उसकी चेक बुक कहीं भी रखना पसंद हो और न हो तो भी

सुरक्षित अभिरक्षा में वह ऐसा अपने जोखिम पर करता है। कोई तो जाली चेक बनाकर किसी का पैसा निकालने का मन बनाया खाता किसी की भी चेक-बुक का उपयोग कर सकता है। ऐसी स्थिति में, चेक-बुक का मालिक, जब तक कि उसने इसमें भाग न लिया हो की वापसी की सुविधा के लिए किसी भी तरीके से साजिश राशि को रखने के लिए किसी भी तरह के कदाचार का आरोप नहीं लगाया जा सकता उसकी चेक-बुक लावारिस है या सुरक्षित अभिरक्षा में नहीं है। इसलिए आरोप का पहला भाग अप्रमाणिक होने के कारण खारिज किया जा सकता है बिना किसी और चीज़ के। आरोप का दूसरा पहलू यह है कि चूँकि अपीलकर्ता ने अपनी चेक-बुक लावारिस छोड़ दी थी अपीलकर्ता लापरवाह था और जानबूझकर अवज्ञा का दोषी था एक सेल्समैन के रूप में अपने कर्तव्यों के पालन में कोई बल नहीं है। किसी की अपनी चेक-बुक को लावारिस रखना इसका कोई हिस्सा नहीं है कर्मचारियों के कर्तव्यों का प्रदर्शन और वहाँ नहीं था नियोक्ता द्वारा आदेश दिया जाए कि अपीलकर्ता को उसे कैसे संभालना चाहिए निजी चेक-बुक. इसलिए, होने से अलग आरोप तुच्छ हास्यास्पद है और इसे फंसाया भी नहीं जा सकता था। भले ही आरोप में आरोप को निर्विवाद छोड़ दिया जाए क्या सड़ांध कदाचार है? नियोक्ता नहीं कर सका उनके समर्थन में बिना किसी सबूत के ऐसे आरोप तय किए गए अभी तक और दूसरा मध्यस्थ उन्हें सिद्ध मानता है। इसलिए दूसरे मध्यस्थ ने जांच के निष्कर्षों को

स्वीकार कर लिया अधिकारी जो स्वयं विकृत थे. दूसरा ही नहीं मध्यस्थ ने प्रस्तुत करने में अपना दिमाग नहीं लगाया अपीलकर्ता ने कहा कि निष्कर्ष विकृत थे लेकिन वह केवल किसी भी तरीके से विश्लेषण किए बिना या उसके आईपीएस दीक्षित को रिकॉर्ड किया गया केवल साक्ष्य खोजने के लिए उसका परीक्षण करना या उस पर अपना दिमाग लगाना यह पता लगाने के लिए कि क्या इसे प्रमाणित करने के लिए कोई सबूत था आरोप लगाएं और क्या कोई उचित व्यक्ति इस पर पहुंचेगा जांच अधिकारी जिस निष्कर्ष पर पहुंचे। पुरस्कार दूसरे मध्यस्थ का, इस तथ्य से अलग कि वह है बिना किसी कानूनी साक्ष्य के आधार पर अतिरिक्त नुकसान होता है मन का पूरी तरह प्रयोग न करने की दुर्बलता। कोई भी खोज सबूतों के पूर्ण अभाव पर आधारित कदाचार गिरना चाहिए।

विवाद यह है कि एक बार दूसरा मध्यस्थ आया था निष्कर्ष यह है कि अपीलकर्ता को पूरा अवसर दिया गया था न तो घरेलू जांच में भाग लेने के लिए उच्च न्यायालय कला के तहत 226 न ही कला के तहत यह न्यायालय।136 बैठ सकते हैं जांच अधिकारी के निष्कर्षों पर अपील करें और साक्ष्यों का पुनर्मूल्यांकन करें, इसमें कोई बल नहीं है। के अभ्यास में धारा द्वारा प्रदत्त क्षेत्राधिकार। 11-औद्योगिक का ए विवाद अधिनियम, 1947 के तहत मध्यस्थ और यह न्यायालय दोनों कर सकते हैं घरेलू पूछताछ में दिए गए सबूतों का पुनर्मूल्यांकन करें और चाहे खुद को संतुष्ट करो नियोक्ता

के नेतृत्व में साक्ष्य ने कदाचार स्थापित किया काम करने वाले के खिलाफ. संघर्ष करने के लिए बहुत देर हो चुकी है कि मध्यस्थ के पास केवल यह निर्णय लेने की शक्ति है कि क्या जांच अधिकारी द्वारा निकाले गए निष्कर्ष विश्वसनीय थे पूछताछ में सामने आए सबूतों से कोई निष्कर्ष निकाला जा सकता है और नहीं स्वयं साक्ष्य की पुनः सराहना करें और उस तक पहुंचें निष्कर्ष कि क्या कदाचार का आरोप लगाया गया है कर्मकार स्थापित किया गया है अथवा नहीं।

मेसर्स फायरस्टोन टायर एंड रबर कंपनी के कर्मचारी इंडिया (पी) लिमिटेड बनाम प्रबंधन और अन्य, [1973] 3 एससीआर 587, करने के लिए भेजा।

यह अच्छी तरह से स्थापित है कि निष्कर्ष कहाँ से मिले कदाचार बिना किसी कानूनी सबूत और निष्कर्ष पर आधारित है वह है जिसके पास कोई भी उचित व्यक्ति, मध्यस्थ, नहीं आएगा धारा के तहत नियुक्त किया गया। 10-ए या इस न्यायालय में कला के तहत अपील। 136 ऐसे निष्कर्षों को विकृत मानकर अस्वीकार कर सकता है। यह मानते हुए कि निष्कर्ष विकृत हैं, इसका पुनर्मूल्यांकन नहीं होता है साक्ष्य, हालाँकि यह न्यायालय बिल्कुल सही होता धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग उचित है। 11ए करना है इसलिए।

गुजरात स्टील ट्यूब्स लिमिटेड बनाम गुजरात स्टील ट्यूब्स मजदूर सभा,[1980] 2 एससीआर 146, संदर्भित।

यह समान रूप से अच्छी तरह से तय है कि जहां एक अर्ध-न्यायिक है ट्रिब्यूनल या मध्यस्थ बिना किसी कानूनी आधार के निष्कर्षों को रिकॉर्ड करता है साक्ष्य और निष्कर्ष या तो उसके आईपीएस दीक्षित हैं या आधारित हैं अनुमानों और अनुमानों पर, जांच प्रभावित होती है दिमाग और स्टैंड का उपयोग न करने की अतिरिक्त दुर्बलता ख़राब किया हुआ. औद्योगिक न्यायाधिकरण या मध्यस्थ या ए अर्ध-न्यायिक प्राधिकारी न केवल ऐसे निष्कर्षों को अस्वीकार कर सकते हैं लेकिन यह भी निष्कर्ष बिना किसी कानूनी सबूत के या यदि ऐसा है तो आधारित है केवल अनुमानों और असंबंधित अनुमानों पर आधारित है

इस आधार पर साक्ष्य कि वे कुल गैर-का खुलासा करते हैं मन का प्रयोग.

मौजूदा मामले में, किसी भी कोण से देखा जाए तो जांच अधिकारी और दूसरे का निष्कर्ष मध्यस्थ पूरी तरह से विकृत हैं और इसलिए टिकाऊ नहीं हैं। उच्च न्यायालय ने जांच करने से इनकार करके स्पष्ट रूप से गलती की थी तर्क यह है कि निष्कर्ष साक्ष्य के मूल्यांकन पर संक्षेप में विकृत थे, विशिष्ट और पूरी तरह से अस्थिर थे।

साक्ष्य के मूल्यांकन और पूर्ण अभाव के बीच सबूत है कि एक सराहनीय अंतर है जो हो सकता है इसे कभी भी नज़रअंदाज़ नहीं किया जाना चाहिए और उच्च न्यायालय को भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए रिट याचिका को शॉर्ट सर्किट कर दिया।

यदि इसके समर्थन में बिल्कुल कोई सबूत नहीं है केवल कदाचार का आरोप अर्थात् लापरवाही का आरोप किसी की निजी चेक-बुक को सुरक्षित अभिरक्षा में रखना निष्कर्ष न केवल विश्वसनीय नहीं है, बल्कि पूर्णतः विश्वसनीय है विकृत है और यह न्यायालय इससे पूरी तरह सहमत है पहले मध्यस्थ द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्ष कि निष्कर्ष जांच अधिकारी विकृत थे और जांच पूरी तरह से गलत थी ख़राब किया हुआ. [880 जी]

869

जहां बर्खास्तगी के आदेश को बरकरार रखने की मांग की गई है घरेलू जांच में एक निष्कर्ष पर जो दिखाया गया है विकृत और गैर-से पीड़ित होने के कारण जांच ख़राब हो गई है दिमाग का प्रयोग ही अदालत के लिए खुला रास्ता तय करना है इसे एक तरफ कर दिया जाए और इसके परिणामस्वरूप बहाली से राहत मिलनी चाहिए मंज़ूर किया गया।

कंपनी का कथन है कि अपीलकर्ता के बाद से उसकी बर्खास्तगी की अवधि के दौरान लाभकारी रूप से नियोजित किया गया था, उसे बकाया वेतन नहीं दिया जाना चाहिए, असफल होना चाहिए। केवल साक्ष्य यह था

कि रोजगार से उसकी जबरन अनुपस्थिति के दौरान अपीलार्थी की सेवा समाप्ति की तिथि से और उसके परिवार के सदस्य उसके पिता के साथ रह रहे थे-ससुराल वाले और इस अवधि के दौरान अपीलकर्ता उसकी मदद कर रहा था ससुर जिनके पास कोयला-डिपो था। इस पर इसका प्रमाण है यह नहीं कहा जा सकता कि अपीलकर्ता को लाभकारी रूप से नियोजित किया गया था बकाया वेतन के दावे को खारिज करने के संबंध में। यदि यह लाभदायक है कंपनी द्वारा दावा किए गए रोजगार के लिए, नियोक्ता ऐसा कर सकता है तर्क है कि बर्खास्त कर्मचारी को अपने पास रखने के लिए शरीर और आत्मा ने मिलकर भीख माँगना शुरू कर दिया था और वह यही होगा साथ ही लाभकारी रोजगार भी मिलेगा। अत: अपीलार्थी पूर्ण बकाया वेतन और सभी परिणामी वेतन पाने का हकदार होगा।

निर्णय:

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 2386/1984।

दिल्ली उच्च न्यायालय रिट याचिका संख्या 314/1983 मे पारित अंतिम निर्णय और आदेश दिनांक 2 मार्च,1983 से उत्पन्न।

अपीलार्थी की ओर से सुश्री ममता सरीन।

प्रतिवादी नंबर 2 के लिए पवन कुमार जैन और केके गुप्ता। अदालत का फैसला देसाई द्वारा सुनाया गया। जे. अपीलकर्ता राजिंदर कुमार किंद्रा को मेसर्स रेमंड वूलन मिल्स लिमिटेड (संक्षेप में 'नियोक्ता') द्वारा

चपरासी के रूप में शामिल किया गया था। 1972 में उन्हें एक सेल्समैन के रूप में पदोन्नत किया गया था और उस समय वह नई दिल्ली के करोल बाग में रेमंड के रिटेल शोरूम में कार्यरत थे। श्री आरएस नेगी उस नियोक्ता के करोल बाग शोरूम के प्रबंधक-सह-कैशियर थे, जिसके अधीन अपीलकर्ता काम कर रहा था। उन्हें 11 दिसंबर, 1975 को एक आरोप-पत्र सौंपा गया, जो इस प्रकार है:

> "श्री राजिंदर किंद्रा, आपको सूचित किया जाता है कि आपने रेमंड्स के रिटेल शो-रूम, 2397/1, हरधिअन सिंह रोड, नई दिल्ली-5 में सेल्समैन के रूप में काम करते हुए रेमंड्स की रकम से नकदी और धन का दुरुपयोग किया है । वूलन मिल्स लिमिटेड ने 10.6.75 से 17.10.75 की अवधि के दौरान 32,196/88 रुपये या उसके एक हिस्से की सीमा तक झूठे खातों में हेराफेरी करके, मिल्स खाते में फर्जी चेक जमा किए या रिटेल के चेस्ट से नकदी ली। डिपो, रेमंड्स रिटेल शोरूम के प्रबंधक-सह-कैशियर, 2397/1, हरधिअन सिंह रोड, करोल बाग, नई दिल्ली के साथ।"

यह कि श्री राजिंदर कुमार किंद्रा ने एक सेल्समैन के रूप में कार्य करते हुए उक्त शो-रूम के प्रबंधक-सह-कैशियर श्री आरएस नेगी के साथ सहायता की, उकसाया, मिलीभगत और साजिश रची और रुपये की राशि

के विभिन्न चेक जारी किए। आपकी चेक बुक से 15,027/75 का गलत उद्देश्य और साजिश यह थी कि इन फर्जी चेकों को मिल्स के खाते में जमा करके कंपनी को उक्त राशि से चूना लगाया जाए और इस तरह खुद को गैरकानूनी लाभ पहुंचाया जाए और मैनेजर की मिलीभगत से कंपनी को गैरकानूनी नुकसान पहुंचाया जाए। सह-कैशियर श्री आर.एस. नेगी। यह कि श्री राजिंदर कुमार किंद्रा ने कंपनी को रुपये की धोखाधड़ी करने के लिए जानबूझकर/लापरवाही से चेक के उपयोगकर्ता को अनुमति दी है। 15,027/75 श्री आरएस नेगी के साथ साजिश में और आप सेल्समैन के रूप में अपने कर्तव्यों के पालन में आदतन लापरवाह और जानबूझकर अवज्ञाकारी रहे हैं।

उपरोक्त आरोपों की जांच के लिए श्री वीके सोनी को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया था। पूछताछ के दौरान, अपीलकर्ता ने अपने खिलाफ लगाए गए आरोपों से इनकार किया। उन्होंने कहा कि नकदी प्रबंधक-सह-कैशियर श्री आरएस नेगी के पास रहती थी और उन्हें काटे गए कुछ चेक और उनके द्वारा जमा किए गए खाते के विवरण के बारे में बताना है। उन्होंने इस बात से इनकार किया कि उन्होंने कोई चेक जारी किया है. उन्होंने इस बात से इनकार किया कि उन्होंने अपने कर्तव्य के पालन में लापरवाही बरती है. नियोक्ता ने प्रबंधन के गवाह के रूप में श्री ओडी शर्मा, श्री जीएल कपूर, श्री वीके मल्होत्रा और श्री नंदन सिंह से पूछताछ की।

अपीलकर्ता ने अपनी ओर से साक्ष्य दिया और नियोक्ता की ओर से उससे जिरह की गई। उन्होंने अपने गवाह के रूप में श्री एके गोडबोले से भी पूछताछ की।

जांच अधिकारी श्री वीके सोनी ने 22 जून, 1976 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। रिपोर्ट में, उन्होंने अन्य बातों के साथ-साथ यह माना कि अपीलकर्ता अपने कर्तव्यों के निर्वहन में घोर लापरवाही और कदाचार का दोषी था और वह धोखाधड़ी करने के लिए सक्रिय रूप से जिम्मेदार था। श्री आर.एस. नेगी के साथ कंपनी पर रु. 15027.75 और अपीलकर्ता के खिलाफ आरोप-पत्र में निहित सभी आरोपों को साबित कर दिया गया। नियोक्ता ने रिपोर्ट स्वीकार कर ली और अपीलकर्ता को 25 अगस्त, 1916 से सेवा से बर्खास्त कर दिया।

अपीलकर्ता ने अन्य बातों के साथ-साथ यह तर्क देते हुए एक औद्योगिक विवाद उठाया कि जांच अधिकारी के निष्कर्ष विकृत थे और लापरवाही या धन के गबन के आरोप के संबंध में कोई सबूत नहीं था और सेवा से बर्खास्तगी पूरी तरह से अनुचित थी। नियोक्ता और अपीलकर्ता एक लिखित समझौते द्वारा अपीलकर्ता की सेवा से बर्खास्तगी से उत्पन्न मौजूदा औद्योगिक विवाद को मध्यस्थ के पास भेजने पर सहमत हुए, जैसा कि धारा द्वारा प्रदान किया गया है। औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 10 (ए) (1) (संक्षेप में अधिनियम)। उपरोक्त लिखित समझौते के अनुसरण में

पहले प्रतिवादी दिल्ली प्रशासन ने निम्नलिखित विवाद को श्रम न्यायालय, दिल्ली के पीठासीन अधिकारी श्री जीसी जैन को भेजा, जिन्हें पक्षकारों द्वारा मध्यस्थ के रूप में चुना गया था। इसे इस प्रकार पढ़ा जाता है:-

"(1) क्या श्री आरके किंड्रा की सेवाएं अवैध और अनुचित तरीके से समाप्त कर दी गईं?

(2) क्या जांच की कार्यवाही प्राकृतिक न्याय और समानता के सिद्धांतों के आधार पर शुरू की गई थी?

(3) कर्मचारी किस राहत का हकदार है, यदि कोई हो?"

नियोक्ता ने मध्यस्थ के समक्ष तर्क दिया कि उसके द्वारा की गई जांच निष्पक्ष और उचित है और अपीलकर्ता को जांच में भाग लेने, प्रबंधन द्वारा प्रस्तुत गवाहों से जिरह करने और अपने साक्ष्य का नेतृत्व करने का पूरा अवसर दिया गया था। आगे यह तर्क दिया गया कि जांच अधिकारी द्वारा पहुंचाए गए निष्कर्ष और उसके द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्ष सबूतों और सबूतों से निकाले गए अनुमेय निष्कर्षों पर आधारित हैं और वे ऐसे हैं कि कोई भी उचित व्यक्ति साक्ष्य के आधार पर अपीलकर्ता के अपराध के निष्कर्ष पर पहुंच जाएगा। . यह प्रस्तुत किया गया कि मध्यस्थ जांच अधिकारी के निष्कर्षों पर अपील में नहीं बैठ सकता। आगे यह तर्क दिया गया कि किसी भी दर पर यह दिखाने के लिए संतोषजनक सबूत हैं कि अपीलकर्ता ने लापरवाही से अपने निजी बैंकिंग खाते के संबंध में अपनी

चेक बुक को इस तरह से रखा ताकि कोई भी इसका दुरुपयोग कर सके और यह जानबूझकर किया गया था। ताकि संभवतः प्रबंधक-सह-कैशियर श्री आरएस नेगी द्वारा धोखाधड़ी को अंजाम देना आसान हो सके। अंतिम विश्लेषणों में यह एकमात्र कदाचार था जिसके लिए वर्तमान अपीलकर्ता को जिम्मेदार ठहराया गया था।

मध्यस्थ ने माना कि नियोक्ता के किसी भी गवाह ने यह नहीं कहा है कि अपीलकर्ता ने कंपनी की किसी भी राशि का दुरुपयोग किया था या उसने झूठे खातों में हेरफेर किया था या नियोक्ता के खाते में फर्जी चेक जमा किए थे या कंपनी के चेस्ट से कोई राशि निकाल ली थी। रिटेल डिपो या श्री आरएस नेगी के साथ सहयोग, सहायता, साजिश या मिलीभगत की थी या कंपनी को धोखा देने के लिए कोई चेक जारी किया था। इस प्रकार नियोक्ता अपीलकर्ता पर किसी भी कदाचार का आरोप लगाने के लिए मध्यस्थ के समक्ष कोई सबूत पेश करने में विफल रहा, जैसा कि आरोप पत्र में आरोप लगाया गया है। मध्यस्थ ने निष्कर्ष निकाला कि आरोप संख्या 1 और 2 के समर्थन में कोई सबूत नहीं था और आरोप संख्या 3 को साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं था। मध्यस्थ द्वारा पहुंचा गया निष्कर्ष निकाला जा सकता है:

> "निष्कर्ष रूप में, मेरा मानना है कि जांच अधिकारी के निष्कर्ष बिना किसी कानूनी सबूत पर आधारित थे और

इसलिए, विकृत थे। इसलिए, जांच दूषित हो गई है। मैं तदनुसार मानता हूं।"

इन निष्कर्षों पर परिणामी आदेश के अलावा कुछ भी नहीं बचता है कि अपीलकर्ता की सेवा से बर्खास्तगी को रद्द कर दिया जाना चाहिए और अलग रखा जाना चाहिए और अपीलकर्ता को सभी परिणामी लाभों के साथ सेवा में बहाल किया जाना चाहिए, जब तक कि नियोक्ता ने अदालत के समक्ष सबूत पेश करने का अवसर नहीं मांगा हो। आरोपों को प्रमाणित करने के लिए मध्यस्थ। ऐसा कोई अवसर नहीं मांगा गया था और इसलिए जैसा कि शंकर चक्रवर्ती बनाम ब्रिटानिया बिस्कुट कंपनी लिमिटेड में इस अदालत ने कहा था, आगे कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं थी और अपीलकर्ता को बहाल करने वाले फैसले का पालन किया जाना चाहिए था। दुर्भाग्य से इस परिणामी आदेश का निर्माण स्थगित कर दिया गया। मध्यस्थ का निष्कर्ष 24 मई, 1976 का है। ऐसा प्रतीत होता है कि इसके तुरंत बाद श्री जीसी जैन मध्यस्थ को दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किया गया और परिणामस्वरूप उन्होंने अपनी शपथ लेने से पहले अंतिम आदेश नहीं दिया जो कि केवल एक औपचारिक हिस्सा था। उसके कर्तव्यों का. दुर्भाग्य से इसके कारण दूसरा संदर्भ आया। इस बार संदर्भ धारा के तहत बनाया गया था। 10 (ए) (1) श्री एनएल कक्कड़, सेवानिवृत्त अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दिल्ली

को मध्यस्थ के रूप में। निर्णय के लिए श्री कक्कड़ को वही तीन बिंदु संदर्भित किये गये। श्री कक्कड़ ने जांच अधिकारी के सामने पेश किए गए सबूतों को बताने के बाद अपने निष्कर्षों को इस प्रकार बताया:-

> "(ए) श्री आरके किंड्रा की सेवाएं अवैध रूप से या अनुचित तरीके से समाप्त नहीं की गईं, बल्कि उनके खिलाफ आरोप सफलतापूर्वक साबित होने के कारण समाप्त की गईं, विशेष रूप से तीसरा आरोप जो जानबूझकर/लापरवाही से चेक के उपयोगकर्ता को अनुमति देने के संबंध में है श्री आरएस नेगी के साथ साजिश करके कंपनी को धोखा दिया और सेल्समैन के रूप में अपने कर्तव्यों के पालन में लापरवाही बरती।
>
> (बी) कि जांच की कार्यवाही प्राकृतिक न्याय और समानता के सिद्धांतों से प्रभावित नहीं हुई थी क्योंकि कर्मचारी को पूरा अवसर दिया गया था और प्रबंधन के किसी भी कार्य से उस पर कोई पूर्वाग्रह नहीं हुआ था, हालांकि उसे अपने साक्ष्य का नेतृत्व करने का पूरा अवसर दिया गया था। और प्रबंधन के गवाहों से जिरह करना और विशेष रूप से काम करने वाले व्यक्ति और जांच अधिकारी के बीच कोई दुश्मनी नहीं थी और बर्खास्तगी गलत नहीं थी।

(सी) यह कि कर्मचारी किसी भी राहत का हकदार नहीं है, और बकाया वेतन और सेवा की निरंतरता के साथ बहाली का हकदार नहीं है क्योंकि वह बर्खास्तगी के बाद से श्री तारा चंद के साथ उनके कोयला डिपो में लाभप्रद रूप से कार्यरत है। पुरस्कार के माध्यम से संदर्भ का तदनुसार उत्तर दिया जाता है।"

अपीलकर्ता ने कला के तहत एक रिट याचिका दायर की। 226 दिल्ली उच्च न्यायालय में श्री कक्कड़ द्वारा दिए गए पुरस्कार की शुद्धता, वैधता और वैधानिकता पर सवाल उठाया गया। उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने मामले को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि मामला साक्ष्य के मूल्यांकन पर निर्भर करता है और न्यायालय कला के तहत इसका पुनर्मूल्यांकन नहीं कर सकता है। संविधान के 226 . अतः विशेष अनुमति द्वारा यह अपील।

शुरुआत में यह बिल्कुल स्पष्ट कर दिया जाए कि अपीलकर्ता पर एकमात्र कदाचार यह था कि उसने अपने निजी खाते के संबंध में अपनी चेक-बुक को इस तरह से रखने में लापरवाही की थी कि इससे श्री आरएस नेगी, प्रबंधक-सह-कैशियर को नुकसान हुआ। संबंधित समय में अपीलकर्ता जिस शाखा में सेल्समैन था, उसने चेक फॉर्म का दुरुपयोग किया और इस तरह नियोक्ता को धोखा दिया। श्री पीके जैन ने विशेष रूप से नियोक्ता के

लिए वकील सीखा यह स्वीकार किया गया कि अपीलकर्ता के खिलाफ कथित एकमात्र कदाचार में उसकी स्वयं की चेक-बुक रखने में लापरवाही शामिल है जिसके द्वारा वह अपने निजी खाते को इस तरह से संचालित कर सकता है ताकि कोई भी व्यक्ति चेक फॉर्म का दुरुपयोग कर सके। उनसे बार-बार पूछा गया कि कौन सा कानून, नियम, विनियम या कोई स्थायी आदेश है, जिसके तहत किसी कर्मचारी को अपनी निजी चेक-बुक को ताले और चाबी या सुरक्षित अभिरक्षा में रखने की आवश्यकता होती है ताकि उसके अलावा कोई भी उस तक पहुंच न सके। और हम व्यर्थ ही उत्तर की प्रतीक्षा करते रहे। यह माना गया कि अपीलकर्ता नियोक्ता के धन के किसी भी गबन या दुरुपयोग का दोषी नहीं है, हालांकि एक भव्य यद्यपि भड़कीला आरोप तय किया गया था कि उसने नियोक्ता के खातों से रुपये की सीमा तक नकदी और धन का दुरुपयोग किया था। 32,196.88 पी. या 10 जून 1975 से 10 अक्टूबर 1975 की अवधि के दौरान झूठे खातों में हेरफेर करके, नियोक्ता के खाते में फर्जी चेक जमा करके या शाखा के प्रबंधक-सह-कैशियर श्री आरएस नेगी के साथ शाखा की छाती से नकदी निकालकर। . अपीलकर्ता द्वारा धन के दुरुपयोग या गबन या खातों में हेरफेर के आरोप के समर्थन में सबूत का कोई सबूत नहीं है। यह शर्तों में स्वीकार किया गया था. विशिष्ट रूप से, नियोक्ता का आरोप यह है कि श्री आरएस नेगी, प्रबंधक-सह-कैशियर ने अपने निजी खाते के संबंध में अपीलकर्ता की चेक-

बुक से चेक फॉर्म का दुरुपयोग किया और नियोक्ता के धन का गबन किया। यह नियोक्ता का मामला नहीं था कि आवेदक ने चेक निकाला या तिजोरी से नकदी का गबन किया। एक अन्य आरोप यह था कि अपीलकर्ता ने शाखा के प्रभारी प्रबंधक-सह-कैशियर श्री आरएस नेगी को उकसाया, सहायता की, उनके साथ मिलीभगत की या साजिश रची और रुपये की राशि के विभिन्न चेक जारी किए। 15,027.75 पी. नियोक्ता के खाते में फर्जी चेक जमा करके नियोक्ता को धोखा देने के गुप्त उद्देश्य से अपना निजी खाता संचालित करने के लिए उसे जारी किए गए अपीलकर्ता की चेक-बुक में निहित चेक के प्रपत्रों पर आहरित किया गया और इस तरह खुद को गलत लाभ और गलत नुकसान हुआ। श्री आर.एस. नेगी की मिलीभगत से नियोक्ता को। फिर से यह माना गया कि ऐसा कोई सबूत नहीं है जो यह संकेत दे सके कि अपीलकर्ता ने स्वयं कोई चेक जारी किया था या उसने किसी को आर फर्जी चेक जारी करने में सहायता या उकसाया था। ये आरोप क्रमांक 1 और 2 में आरोप थे और श्री कक्कड़ का यह निष्कर्ष कि वे साबित हो गए हैं, स्वयं नियोक्ता की स्वीकारोक्ति पर विकृत माना जा सकता है क्योंकि घरेलू जांच के दौरान एक भी गवाह ने ऐसा नहीं कहा। प्रतिवादी के विद्वान वकील श्री जैन इन दोनों आरोपों के समर्थन में साक्ष्य का एक भी वाक्य नहीं बता सके।

श्री पीके जैन ने आग्रह किया कि तीसरा आरोप जो इस आशय का था कि अपीलकर्ता ने नियोक्ता को धोखा देने के लिए बैंक द्वारा उसे जारी की गई चेक-बुक से चेक का उपयोग करने की अनुमति दी थी जिसमें वह अपना निजी खाता बनाए हुए था। रुपये का 15,027.75 पी. श्री आरएस नेगी के साथ साजिश में और यह कि वह लापरवाह थे और एक सेल्समैन के रूप में अपने कर्तव्यों के गलत प्रदर्शन के लिए जानबूझकर अवज्ञा के दोषी थे, प्रमाणित किया गया था। यह एक समग्र प्रभार है. आरोप का पहला भाग उनकी निजी चेक बुक को संभालने में लापरवाही को संदर्भित करता है ताकि श्री आरएस नेगी के साथ साजिश में अपीलकर्ता को अपने निजी खाते के संचालन के लिए जारी की गई चेक-बुक में मौजूद चेक फॉर्म का उपयोग श्री आरएस नेगी द्वारा नियोक्ता को धोखा देने के लिए किया जा सके। गलत तरीके से इस्तेमाल की गई भाषा को खारिज करते हुए आरोप यह है कि अपीलकर्ता ने अपनी निजी चेक बुक को लावारिस रखा या सुरक्षित हिरासत में नहीं रखा ताकि श्री आरएस नेगी ने इस चेक बुक से चेक फॉर्म का दुरुपयोग किया। इस आरोप के समर्थन में, सबूत यह है कि अपीलकर्ता ने अपनी चेक-बुक को ताले और चाबी के नीचे या सुरक्षित अभिरक्षा में नहीं रखा था ताकि उसके अलावा किसी और को उस तक पहुंच न हो, हम सराहना करने के अलावा इसे समझ नहीं पाए हैं। यह आरोप. जब किसी खातेधारक को बैंक द्वारा चेक बुक जारी की जाती है, तो

ऐसा कोई कानून नहीं है जिसके तहत उसे अपनी चेक बुक सुरक्षित हिरासत में रखने की आवश्यकता हो। वह इसे किसी भी तरीके से रख सकता है और यदि इस प्रक्रिया में कोई चेक का दुरुपयोग करता है और धारक के खाते से पैसे निकाल लेता है, तो बैंक खाता धारक की लापरवाही का आरोप लगाते हुए अपनी देनदारी से इनकार कर सकता है। कोई भी व्यक्ति अपनी चेक बुक अपनी इच्छानुसार कहीं भी रख सकता है और भले ही वह सुरक्षित अभिरक्षा में न हो, वह ऐसा अपने जोखिम पर करता है। चेक बुक के लापरवाहीपूर्वक संचालन के परिणामस्वरूप दुरुपयोग की स्थिति में, यदि कोई व्यक्ति चेक के प्रपत्रों का दुरुपयोग करके उस खाते से कोई राशि निकाल लेता है जिसके संबंध में चेक बुक जारी की गई है, तो बैंक अपनी देनदारी से इनकार कर सकेगा। यहां पर यह मामला नहीं है। आरोप यह है कि अपीलकर्ता ने अपनी चेक बुक इस तरह से रखी थी कि कोई भी उसकी पहुंच में न हो और किसी ने बेईमानी से अपीलकर्ता की चेक बुक से चेक के फॉर्म हटा दिए और उनका उपयोग अपीलकर्ता के खाते से पैसे निकालने के लिए किया। नियोक्ता का खाता. कोई व्यक्ति फर्जी चेक बनाने और किसी के खाते से पैसे निकालने के लिए किसी की भी चेक बुक का इस्तेमाल कर सकता है। ऐसी स्थिति में, चेक बुक के मालिक को, जब तक कि उसने राशि की निकासी की सुविधा के लिए किसी भी तरह से साजिश में भाग नहीं लिया हो, उसकी चेक बुक को लावारिस रखने या

सुरक्षित हिरासत में नहीं रखने के लिए किसी भी तरह के कदाचार के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है। आरोप क्रमांक 3 के प्रथम अंग को बिना किसी और बात के अप्रमाणिक मानकर खारिज किया जा सकता है।

तीसरे आरोप का दूसरा पहलू यह है कि अपीलकर्ता एक सेल्समैन के रूप में अपने कर्तव्यों के पालन में लापरवाह और जानबूझकर अवज्ञा का दोषी था। एक भी गवाह ने अपीलकर्ता की ओर से अपने कर्तव्यों के पालन में किसी लापरवाही की बात नहीं कही है। इस आशय के साक्ष्य में दूर-दूर तक कोई सुझाव नहीं है। एक भी गवाह ने कर्तव्य पालन में जानबूझकर अवज्ञा की बात नहीं कही है। ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ भड़कीले आरोप सच्चाई की परवाह किए बिना या जिम्मेदारी की परवाह किए बिना नियोक्ता द्वारा गढ़े गए हैं, इस तरह के घृणित आरोप लगाना और इसके समर्थन में ज़रा भी सबूत के बिना गंभीर आरोप लगाना, हमने श्री पीके जैन से बार-बार पूछा, सीखा नियोक्ता के वकील को जांच अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत साक्ष्यों से यह दिखाना होगा कि नियोक्ता के किस आदेश की अपीलकर्ता ने अनिच्छा से अवज्ञा की थी, साथ ही लापरवाही को उजागर करने के लिए कर्तव्य के पालन में चूक और कमीशन का कार्य भी किया था। हमें जो एकमात्र उत्तर मिला वह यह था कि अपीलकर्ता ने अपनी चेक बुक लावारिस रखी थी। अपनी स्वयं की चेक बुक को लावारिस रखना कर्मचारी के कर्तव्यों के पालन का हिस्सा नहीं है और नियोक्ता द्वारा कोई आदेश नहीं

दिया गया था कि अपीलकर्ता को अपनी निजी चेक बुक को कैसे संभालना चाहिए।

यह स्पष्ट रूप से स्पष्ट कर दिया जाए कि यह न्यायालय इस अपील में साक्ष्यों की दोबारा सराहना नहीं कर रहा है। श्री जीसी जैन, पहले मध्यस्थ जिन्होंने धारा के तहत उन्हें दिए गए संदर्भ में जांच का एक बड़ा हिस्सा पूरा किया। 10 (ए) (1) जांच कार्यवाही में नियोक्ता की ओर से दिए गए सबूतों की सावधानीपूर्वक जांच करने के बाद निम्नानुसार निष्कर्ष निकाला गया: -

> "22. मैंने इस पूरे साक्ष्य की सावधानीपूर्वक जांच की है। किसी भी गवाह ने यह नहीं कहा है कि श्री किंड्रा ने कंपनी की किसी भी राशि का दुरुपयोग किया था या उन्होंने झूठे खातों में हेरफेर किया था, या मिल के खाते में फर्जी चेक जमा किए थे और किसी भी राशि को निकाल लिया था। रिटेल डिपो की चेस्ट या श्री आरएस नेगी के साथ सहयोग, सहायता की साजिश या मिलीभगत थी या कंपनी को धोखा देने के लिए कोई चेक जारी किया था। पीडब्लू-1 ने पीडब्लू-3 को जो कहा वह यह है कि श्री नेगी ने इस कर्मचारी की चेक बुक से पांच चेक का उपयोग किया था कंपनी को धोखा देने के लिए। श्री किंड्रा की ओर से कोई धोखाधड़ी

दिखाने या उन्हें श्री नेगी द्वारा किए गए गबन से जोड़ने का कोई सबूत नहीं है। केवल यह तथ्य कि उनके चेक का उपयोग किया गया था, यह मानने के लिए पर्याप्त नहीं है कि उन्होंने श्री के साथ साजिश रची थी नेगी या कि उन्होंने जानबूझकर या लापरवाही से कंपनी को रुपये की धोखाधड़ी करने के लिए चेक के उपयोग की अनुमति दी।

15,027.75 पी. या उसके कुछ भाग में प्रबंधन के स्वयं के गवाह ने कहा है कि इन चेकों का उपयोग या तो श्री आरके किंड्रा की मिलीभगत से या इसके संबंध में उनकी लापरवाही के कारण किया गया था। उनमें से किसी ने भी निश्चितता के साथ नहीं कहा है कि श्री किंड्रा इस हेराफेरी में एक पक्ष थे। इसमें कोई संदेह नहीं है कि साक्ष्य से पता चलता है कि वह अपनी चेक बुक को ताले और चाबी के नीचे रखने में बहुत सावधान नहीं थे। लेकिन यह परिस्थिति यह मानने के लिए पर्याप्त नहीं है कि उन्होंने श्री आरएस नेगी के साथ कोई साजिश रची थी या हेराफेरी में भागीदार थे। इस प्रकार आरोप संख्या 1 और 2 के समर्थन में कोई सबूत नहीं था। इस बात का कोई सबूत नहीं है कि श्री किंड्रा ने जानबूझकर उपयोगकर्ता को अपनी चेक बुक की अनुमति दी थी। इस

बात का कोई सबूत नहीं है कि चेक बुक को बिना ताले वाली दराज में रखने में उनकी लापरवाही कंपनी को धोखा देने के उद्देश्य से थी। इस बात का कोई सबूत नहीं है कि वह अपने कर्तव्यों के निर्वहन में आदतन लापरवाह या जानबूझकर अवज्ञाकारी था। उनकी व्यक्तिगत चेक बुक रखने का तरीका सेल्समैन के रूप में उनके कर्तव्यों का हिस्सा नहीं था। इस प्रकार आरोप संख्या 3 को भी साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं था"

उन्होंने अपने पुरस्कार के अनुच्छेद 23 में आगे निष्कर्ष निकाला कि जांच अधिकारी के निष्कर्ष बिना किसी कानूनी सबूत पर आधारित थे और इसलिए विकृत थे और जांच ख़राब हो गई थी। नियोक्ता ने कभी भी आरोपों को साबित करने के लिए मध्यस्थ के समक्ष साक्ष्य पेश करने का अवसर नहीं मांगा। वास्तव में श्री जीसी जैन द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्ष पर उन्हें बर्खास्तगी के आदेश को रद्द करने और बकाया वेतन के साथ बहाली का निर्देश देने का परिणामी आदेश देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने अनावश्यक रूप से विलंब किया और फिर इससे पहले कि वह शेष कार्य में भाग ले पाते, उन्हें हटा दिया गया। अपीलकर्ता को नई जांच और नए मध्यस्थ द्वारा पूर्ण अपमान का सामना करने के लिए छोड़ कर दिल्ली उच्च न्यायालय की पीठ में पदोन्नत किया गया।

श्री का ताजा संदर्भ दिया गया। नियोक्ता के वकील एनएल कक्कड़, श्री पीके जैन ने तर्क दिया कि यह न्यायालय केवल श्री कक्कड़ के पुरस्कार से संबंधित है और श्री जीसी जैन द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्ष प्रासंगिक नहीं हैं। इस प्रस्तुतिकरण के बारे में हमें गंभीर आपत्तियां हैं, लेकिन इस मामले में उस बिंदु पर निर्णय लेना आवश्यक नहीं है। अब हम खुद को श्री कक्कड़ के पुरस्कार तक ही सीमित रखेंगे।

पैराग्राफ 1 से 5 में, विवाद का इतिहास और आरोप श्री कक्कड़ द्वारा अपीलकर्ता के विरुद्ध आरोप तय किये गये हैं। पैराग्राफ 6 जांच अधिकारी ने क्या किया उससे संबंधित है। पैराग्राफ 7 अपीलकर्ता की ओर से तर्कों को पुनः प्रस्तुत करता है। अनुच्छेद 8 नियोक्ता की ओर से तर्कों का सारांश प्रस्तुत करता है। पैराग्राफ 9, 10 और 11 जांच के तरीके से संबंधित हैं। अनुच्छेद 12 नियोक्ता की ओर से प्रस्तुत लिखित तर्कों को संदर्भित करता है। अंतिम पैराग्राफ 13 में, श्री कक्कड़ कहते हैं कि मामले की परिस्थितियाँ और पार्टियों द्वारा जांच अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किए गए साक्ष्य के साथ-साथ वर्तमान कार्यवाही में और दायर और साबित किए गए दस्तावेजों पर विचार करने पर, यह माना जाता है कि कहा गया. इसके बाद उन्होंने सबूतों या इसकी पूर्ण अनुपस्थिति पर चर्चा नहीं करते हुए अपनी आईपीएसी दीक्षित को रिकॉर्ड किया। यह बताया जा सकता है कि जांच अधिकारी श्री यूके सोनी द्वारा अपीलकर्ता के खिलाफ की गई जांच

के दौरान, नियोक्ता ने 4 गवाहों अर्थात् श्री ओडी शर्मा, श्री जीएल कपूर, श्री वीके मल्होत्रा और श्री नंदन सिंह की जांच की थी। श्री जीसी जैन के समक्ष किसी भी गवाह की जांच नहीं की गई और नियोक्ता ने जांच अधिकारी की रिपोर्ट और जांच अधिकारी द्वारा दर्ज किए गए चार गवाहों के साक्ष्य पर भरोसा किया। जब मामला श्री कक्कड़ के समक्ष आया, तो नियोक्ता ने किसी भी गवाह से पूछताछ नहीं की थी, बल्कि जांच अधिकारी की रिपोर्ट और उपरोक्त गवाहों के साक्ष्य प्रस्तुत किए थे। इसलिए जब मध्यस्थ के समक्ष यह तर्क दिया गया कि चार गवाहों के साक्ष्य को स्वीकार करते हुए भी मानो चुनौती न दी गई हो, कोई भी उचित व्यक्ति कभी भी इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकता है कि अपीलकर्ता पर आरोप संख्या 1, 2 और 3 में लगाए गए कदाचार के बारे में नहीं कहा जा सकता है। साबित करने के लिए, सबूतों की जांच करना उस पर निर्भर था। हमने श्री पीके जैन को यह बताने के लिए आमंत्रित किया कि गबन के आरोप और धन के कथित दुरुपयोग से संबंधित आरोप के समर्थन में कौन से सबूत पर भरोसा किया जा रहा है। वह किसी भी सबूत पर हाथ नहीं डाल सका. यह स्वीकार करते हुए कि गबन और धन के दुरुपयोग के आरोप के समर्थन में कोई सबूत नहीं है, साथ ही यह भी स्वीकार किया कि आरोप संख्या 1 और 2 साबित नहीं हुए हैं, उन्होंने बार-बार इस बात पर जोर दिया कि अपीलकर्ता एकमात्र आचरण के लिए दोषी है, क्योंकि अपीलकर्ता ने जानबूझकर ऐसा

किया था। उसकी चेक बुक किसी के पास नहीं है, जो उसका दुरुपयोग कर सकता है और यह कर्तव्य पालन में लापरवाही है। दोहराव की कीमत पर भी, हमें यह बताना होगा कि किसी भी तरह से अपनी निजी चेक बुक रखना कोई मामूली बात नहीं है। कर्मचारी के कर्तव्य पालन का. कम से कम यह कहा जा सकता है कि यह आरोप तुच्छ होने के अलावा हास्यास्पद है और इसे फंसाया भी नहीं जा सकता था। यदि आरोप में आरोप को निर्विवाद छोड़ दिया जाए तो भी यह कदाचार नहीं बनता है। नियोक्ता अभी तक उनके समर्थन में किसी सबूत के बिना ऐसे आरोप तय नहीं कर सका है श्री कक्कड़ इन्हें सिद्ध मानते हैं। इसलिए श्री कक्कड़ ने जांच अधिकारी के निष्कर्षों को स्वीकार कर लिया जो वास्तव में विकृत थे। न केवल श्री कक्कड़ ने अपीलकर्ता के इस कथन पर अपना दिमाग नहीं लगाया कि निष्कर्ष विकृत थे, बल्कि उन्होंने बिना किसी विश्लेषण या जांच के या सबूतों पर अपना दिमाग लगाए बिना केवल यह पता लगाने के लिए कि क्या कोई सबूत था, अपना आईपीएस दीक्षित दर्ज किया। आरोप को प्रमाणित करने के लिए और क्या कोई उचित व्यक्ति उस निष्कर्ष पर पहुंचेगा जिस पर जांच अधिकारी पहुंचा था। श्री कक्कड़ का पुरस्कार, इस तथ्य के अलावा कि यह किसी भी कानूनी सबूत पर आधारित नहीं है, दिमाग के पूर्ण गैर-प्रयोग की अतिरिक्त दुर्बलता से ग्रस्त है। साक्ष्य के पूर्ण अभाव के आधार पर कदाचार का कोई भी निष्कर्ष विफल होना चाहिए।

श्री जैन ने तर्क दिया कि एक बार श्री कक्कड़ इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि अपीलकर्ता को कला के तहत न तो उच्च न्यायालय की घरेलू जांच में भाग लेने का पूरा अवसर दिया गया था। 226 न ही कला के तहत यह न्यायालय । 136 जांच अधिकारी के निष्कर्षों पर अपील कर सकता है और सबूतों का पुनर्मूल्यांकन कर सकता है। हालाँकि हमने सेकंड द्वारा प्रदत्त क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हुए साक्ष्यों की दोबारा सराहना करने का बिल्कुल भी प्रयास नहीं किया है। 11-औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के ए, मध्यस्थ और यह अदालत दोनों घरेलू जांच में दिए गए सबूतों का पुनर्मूल्यांकन कर सकते हैं और खुद को संतुष्ट कर सकते हैं कि क्या नियोक्ता के नेतृत्व वाले सबूतों ने कामगार के खिलाफ कदाचार स्थापित किया है। यह तर्क देने के लिए बहुत देर हो चुकी है कि मध्यस्थ के पास केवल यह तय करने की शक्ति है कि जांच अधिकारी द्वारा पहुंचाए गए निष्कर्ष जांच में दिए गए सबूतों से निकाले जाने योग्य थे या नहीं, न कि सबूतों की दोबारा सराहना करने और निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए। निष्कर्ष यह है कि कर्मचारी के विरुद्ध कथित कदाचार सिद्ध हो गया है या नहीं। मैसर्स फायरस्टोन टायर रबर कंपनी ऑफ इंडिया (पी) लिमिटेड के वर्कमेन बनाम प्रबंधन और अन्य मामले में इस अदालत ने कहा कि धारा की शुरूआत के बाद से। औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 में 11-ए औद्योगिक न्यायाधिकरण अब घरेलू जांच में सबूतों का पुनर्मूल्यांकन करने

और खुद को संतुष्ट करने की शक्तियों से लैस है कि क्या नियोक्ता द्वारा भरोसा किया गया उक्त सबूत कामगार के खिलाफ कथित कदाचार को स्थापित करता है। यह समान रूप से अच्छी तरह से तय है कि धारा के तहत नियुक्त मध्यस्थ। 10-ए को सेकंड में समझा जाता है। 11-ए. गुजरात स्टील ट्यूब्स लिमिटेड बनाम गुजरात स्टील ट्यूब्स मजदूर सभा मामले में इस अदालत ने माना कि धारा के तहत एक मध्यस्थ नियुक्त किया गया था। 10-औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा में समझा गया है। 11-ए और मध्यस्थ संदर्भ सेक के अलावा। 11-ए का दायरा पूर्ण है। इसलिए यह मध्यस्थ के साथ-साथ इस अदालत दोनों के अधिकार क्षेत्र में होगा कि साक्ष्य की दोबारा सराहना की जाए, हालांकि इस मामले में ऐसा करना आवश्यक नहीं है। इस प्रकार यह अच्छी तरह से स्थापित है कि जहां कदाचार के निष्कर्ष बिना किसी कानूनी सबूत पर आधारित होते हैं और निष्कर्ष ऐसा होता है जिस पर कोई भी उचित व्यक्ति नहीं पहुंच सकता है, तो धारा के तहत मध्यस्थ नियुक्त किया जाता है। 10-ए या इस अदालत में कला के तहत अपील। 136 ऐसे निष्कर्षों को विकृत मानकर अस्वीकार कर सकता है। यह मानना कि निष्कर्ष विकृत हैं, साक्ष्य के पुनर्मूल्यांकन का गठन नहीं करता है, हालांकि ऐसा करने के लिए हम धारा 11-ए द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में पूरी तरह से उचित होंगे।

यह भी समान रूप से अच्छी तरह से स्थापित है कि जहां एक अर्ध-न्यायिक न्यायाधिकरण या मध्यस्थ बिना किसी कानूनी सबूत के आधार पर निष्कर्षों को रिकॉर्ड करता है और निष्कर्ष या तो उसके आईपीएस दीक्षित हैं या अनुमानों और अनुमानों पर आधारित हैं, जांच दिमाग के गैर-प्रयोग की अतिरिक्त दुर्बलता से ग्रस्त है और ख़राब खड़ा है. औद्योगिक न्यायाधिकरण या मध्यस्थ या एक अर्ध-न्यायिक प्राधिकरण न केवल ऐसे निष्कर्षों को अस्वीकार कर सकता है, बल्कि बिना किसी कानूनी साक्ष्य के आधार पर निष्कर्ष भी निकाल सकता है या यदि यह केवल अनुमानों और अनुमानों पर आधारित है, जो इस आधार पर साक्ष्य से संबंधित नहीं हैं कि वे पूर्ण गैर-आवेदन का खुलासा करते हैं। मन की। किसी भी कोण से देखने पर, जांच अधिकारी के साथ-साथ मध्यस्थ श्री कक्कड़ का निष्कर्ष पूरी तरह से विकृत है और इसलिए टिकाऊ नहीं है। उच्च न्यायालय, हमारी राय में, इस तर्क की जांच करने से इनकार करने में स्पष्ट रूप से गलती कर रहा था कि निष्कर्ष संक्षिप्त, विशिष्ट और पूरी तरह से अस्थिर आधार पर विकृत थे कि मामला साक्ष्य के मूल्यांकन पर निर्भर करता है।

साक्ष्यों के मूल्यांकन और साक्ष्यों के पूर्ण अभाव के बीच एक सराहनीय अंतर है जिसे कभी भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है और उच्च न्यायालय को रिट याचिका को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए।

यदि समर्थन का कोई सबूत नहीं है या कदाचार का एकमात्र आरोप है, अर्थात् किसी की निजी चेक बुक को सुरक्षित हिरासत में न रखने में लापरवाही, तो निष्कर्ष न केवल विश्वसनीय नहीं है, बल्कि यह पूरी तरह से विकृत है और हम दर्ज किए गए निष्कर्षों से पूरी तरह सहमत हैं। श्री जीसी जैन ने कहा कि जांच अधिकारी के निष्कर्ष विकृत थे और जांच पूरी तरह से दूषित थी।

जहां घरेलू जांच में किसी निष्कर्ष पर बर्खास्तगी के आदेश को कायम रखने की मांग की जाती है, जिसे विकृत दिखाया गया है और जांच दिमाग के गैर-प्रयोग से पीड़ित होने के कारण खराब हो गई है, हमारे लिए एकमात्र रास्ता इसे रद्द करना और परिणामस्वरूप राहत देना है। बहाली की अनुमति दी जानी चाहिए और हमें इस बारे में कुछ भी नहीं बताया गया कि हमें इसकी अनुमति क्यों नहीं देनी चाहिए।

अपीलकर्ता की ओर से अगली दलील दी गई कि उसे पूरे बकाया वेतन के साथ बहाली प्रदान की जाए। नियोक्ता के विद्वान वकील श्री पीके जैन ने यह कहते हुए प्रतिवाद किया कि यह दिखाने के लिए सबूत हैं कि अपीलकर्ता सेवा समाप्ति के बाद से लाभकारी रूप से नियोजित था और इसलिए वह बकाया वेतन का हकदार नहीं था। इस दलील के समर्थन में श्री जैन ने बताया कि अपीलकर्ता ने अपनी जिरह में स्वीकार किया है कि अपनी सेवा समाप्ति की तारीख से रोजगार से जबरन अनुपस्थिति के

दौरान, वह अपने ससुर तारा की मदद करके अपने परिवार का भरण-पोषण कर रहा था। चंद जो एक कोयला डिपो का मालिक है, और वह और उसके परिवार के सदस्य अपने ससुर के साथ रहते थे और उनके पास भरण-पोषण का कोई वैकल्पिक स्रोत नहीं था। यदि यह लाभकारी रोजगार है, तो नियोक्ता यह तर्क दे सकता है कि बर्खास्त कर्मचारी ने अपने शरीर और आत्मा को बनाए रखने के लिए भीख मांगना शुरू कर दिया था और यह भी एक लाभदायक रोजगार होगा। नियोक्ता ने जिस घोर विकृति के साथ इस मामले को देखा, उसने हमें स्तब्ध कर दिया है। यदि सेवा समाप्ति के पूर्णतया अस्थिर आदेश के बाद नियोक्ता इस आधार पर पिछला वेतन देने से इनकार करना चाहता है कि अपीलकर्ता और उसके परिवार के सदस्य अपीलकर्ता के ससुर के साथ रह रहे थे क्योंकि भरण-पोषण का कोई वैकल्पिक स्रोत नहीं था और इस अवधि के दौरान अपीलकर्ता अपने ससुर तारा चंद की मदद कर रहा था, जिनके पास कोयला-डिपो था, यह नहीं कहा जा सकता कि अपीलकर्ता लाभकारी रूप से नियोजित था। यह इस दलील के समर्थन में एकमात्र सबूत था कि सेवा से जबरन अनुपस्थिति के दौरान उसे लाभकारी रूप से नियोजित किया गया था। इसे लाभकारी रोज़गार नहीं कहा जा सकता ताकि बकाया वेतन के दावे को ख़ारिज कर दिया जाए। यह दिखाने के लिए रिकॉर्ड पर कोई सबूत नहीं है कि अपीलकर्ता को सेवा से अनुपस्थिति की अवधि के दौरान लाभकारी रूप से

नियोजित किया गया था। इसलिए, अपीलकर्ता पूर्ण बकाया वेतन और सभी परिणामी लाभों का हकदार होगा।

तदनुसार, अपील की अनुमति दी जाती है और मध्यस्थ श्री कक्कड़ के फैसले को रद्द कर दिया जाता है और अपीलकर्ता को पूर्ण बकाया वेतन और परिणामी लाभों के साथ सेवा में बहाल किया जाता है, जिसके वह हकदार होते अगर उसे गैरकानूनी तरीके से सेवा से बाहर नहीं किया गया होता।, और इस अपील की लागत रुपये निर्धारित की गई। 3,000. अपीलकर्ता को देय बकाया वेतन और इसमें दी गई लागत का भुगतान आज से 2 महीने के भीतर किया जाएगा। अपीलकर्ता को आज से एक सप्ताह के भीतर सेवा में शारीरिक रूप से बहाल कर दिया जाएगा। अपीलकर्ता अपनी निरंतर सेवा के सभी परिणामी लाभों का हकदार होगा।

एचएसके

अपील की अनुमति दी गई।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल टूल सुवास की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी विनीत कुमार मीना (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया।

अस्वीकरणः यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानिय भाषा में अनुवादित किया गया है ओर किसी अन्य उददेश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक ओर अधिकारिक उददेश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा ओर निष्पादन व कार्यान्वयन के उददेश्य से अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।